"33"
pib.nic.in
mod.nic.in

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)
भारत सरकार
****
'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः आश्विन **08, 1944**
शुक्रवारः 30 सितंबर **2022**

रक्षा मंत्री ने संचालन का एक वर्ष पूरा होने पर आयुद्ध निर्माणी बोर्ड से अलग होकर बनी सात रक्षा कंपनियों के कामकाज की समीक्षा की

स्वायत्तता और जवाबदेही के साथ काम करते हुए लाभांश देने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए उनकी सराहना की

श्री राजनाथ सिंह ने डीपीएसयू से भारत को एक वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों को विकसित करने/अपनाने का आह्वान किया

हमारा लक्ष्य 2025 तक 35,000 करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात का लक्ष्य हासिल करना है; लक्ष्य को प्राप्त करने में डीपीएसयू को योगदान देना चाहिएः रक्षा मंत्री

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 30 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) से अलग होकर बनी सात रक्षा कंपनियों के संचालन का एक वर्ष पूरा होने पर उनके कामकाज की समीक्षा की। इन कंपनियों ने 15 अक्टूबर 2021 को 'विजयदशमी' के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किए जाने से पहले 01 अक्टूबर 2021 से संचालन शुरू किया था।

बैठक के दौरान रक्षा उत्पादन विभाग के अधिकारियों ने रक्षा मंत्री को पिछले एक वर्ष में इन नए डीपीएसयू द्वारा की गई प्रगति के बारे में जानकारी दी। सात कंपनियों के अधिकारियों और कर्मचारियों को आभासी रूप से संबोधित करते हुए, श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आयुद्ध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण इन संस्थाओं की वास्तविक क्षमता का उपयोग करके देश को 'आत्मनिर्भर' बनाने के लिए एक बड़ा सुधार था। उन्होंने इस तथ्य की सराहना की कि ये कंपनियां अपने कर्मचारियों के

हितों की रक्षा करते हुए पूर्ण स्वायत्तता, दक्षता और जवाबदेही के साथ प्रगति के पथ पर सुचारू रूप से आगे बढ़ रही हैं, जिसके आधार पर सरकार ने आयुद्ध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण का निर्णय लिया था।

रक्षा मंत्री ने कहा, "पूर्ववर्ती आयुद्ध निर्माणी बोर्ड अपनी बुनियादी संरचना और कुशल जनशक्ति के साथ, देश की एक रणनीतिक संपत्ति थी, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा में मूल्यवान योगदान दिया। तथापि, पिछले कुछ दशकों में सशस्त्र सेनाओं की उच्च लागत, असंगत गुणवत्ता और उत्पादों की पूर्ति में विलंब के संबंध में चिंताएं थीं। एक सरकारी विभाग होने के नाते, आयुद्ध निर्माणी बोर्ड के पास लाभांश देने के लिए बहुत कम स्त्रोत थे। सदियों पुरानी प्रक्रियाएं, प्रथाएं, कागजी काम और नियम एवं विनियम थे, जो प्रासंगिकता नही थे। इन प्रथाओं से छुटकारा पाना समय की मांग थी और निगमीकरण आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका था। सरकार शुरू से ही इन कंपनियों का मार्गदर्शन या समर्थन कर रही है। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि वे प्रगति कर रही हैं।"

आधुनिकीकरण के लिए वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान इन कंपनियों को शेयर/इक्विटी के रूप में 2,953 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और पूंजीगत व्यय के लिए 2026-27 तक इन कंपनियों को 6,270 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी करने की योजना है। इसके अलावा आपात प्राधिकृत निधि के रूप में इन कंपनियों को 3,750 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

इन नई कॉरपोरेट संस्थाओं को प्रदान की गई कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता, सरकार द्वारा मार्गदर्शन व सहयोग के साथ, उनके प्रदर्शन में दिखाई देने लगी है। छह महीने की छोटी सी अवधि यानी 01 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 के भीतर, इन नई कंपनियों ने 8,400 करोड़ रुपये से अधिक का टर्नओवर हासिल किया है, जो पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान पूर्ववर्ती आयुद्ध निर्माणी बोर्ड के निर्गम के मूल्य को देखते हुए महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भी सात नए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने संचयी बिक्री लक्ष्य लगभग 17,000 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है जो पूर्ववर्ती आयुद्ध निर्माणी बोर्ड की पिछली उपलब्धियों की तुलना में काफी अधिक है।

01 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 की अवधि के लिए उत्पादन उपलब्धि की तुलना में लगभग 5,028 करोड़ रुपये, नए डीपीएसयू ने वित्त वर्ष 2022-23 के पहले छह महीनों में 6,500 करोड़ रुपये से अधिक की उत्पादन उपलब्धि दर्ज

की है। निगमीकरण के बाद, नई संस्थाओं ने बदले हुए कॉर्पोरेट सेट अप में उत्पादकता और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। वित्त वर्ष 2021-22 में सात में से छह कंपनियों ने अस्थायी वित्तीय विवरण के आधार पर मुनाफे का संकेत दिया है।

इन सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के कामकाज में और सुधार लाने के लिए श्री राजनाथ सिंह ने कुछ प्रमुख क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान युग को प्रौद्योगिकी संचालित बताते हुए उन्होंने कंपनियों से नवीनतम प्रौद्योगिकियों को विकसित करने या उनसे परिचित होने का आह्वान किया, जो रक्षा उद्योग के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने उनसे घरेलू अनुसंधान और विकास के माध्यम से आधुनिकीकरण पर विशेष जोर देने का आग्रह किया क्योंकि यह आगे बढ़ने का सबसे मजबूत और सुरक्षित तरीका है।

रक्षा मंत्री ने दुनिया भर में भारत की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयासों में योगदान देना कंपनियों का उत्तरदायित्व बताया। उन्होंने कंपनियों से प्रतिस्पर्धी बोली के वर्तमान समय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उत्साही और प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ रणनीतियों को तैयार करने और कार्यान्वित करने का आह्वान किया।

श्री राजनाथ सिंह ने पूंजी निवेश को एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू बताया, जिसके संदर्भ में सरकार वर्तमान में कंपनियों का मार्गदर्शन और समर्थन कर रही है। हालांकि, उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में, डीपीएसयू को अपनी आकांक्षाओं के अनुसार आने वाले समय में बाजार से पूंजी जुटाने में सक्षम होना चाहिए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'आत्मनिर्भर भारत' की परिकल्पना को साकार करने हेतु आयात निर्भरता को कम करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा दिए जा रहे उपायों पर प्रकाश डालते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि निर्यात बढ़ाने में योगदान देना डीपीएसयू का उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा, "आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रक्षा विनिर्माण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक एयरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं तथा सेवाओं में 1.75 लाख करोड़ रुपये का टर्नओवर हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 35,000 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल

है। डीपीएसयू को लक्ष्य हासिल करने और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए।"

श्री राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में कंपनियां टर्नओवर, लाभप्रदता, बाजार मूल्यांकन और समग्र वृद्धि में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेगी। उन्होंने कंपनियों को बल वर्धक के रूप में करार दिया जो देश के रक्षा उत्पादन को आगे ले जाएंगे और विश्व मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करेंगे।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा, "भारत वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ, हमारा उद्देश्य भारत को डिजाइन, उत्पादन, निर्यात के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष देशों में से एक बनाना है। आज जब हमारा देश 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा रक्षा निर्यात पिछले 7-8 वर्षों की तुलना में 5-6 गुना बढ़कर 13,000 करोड़ रुपये हो गया है। नए प्रबंधन को घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ विदेशों में नए अवसरों को तलाशना चाहिए।" उन्होंने उम्मीद जताई कि नई कंपनियां रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी प्रणाली को मजबूत बनाने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

- स्थापना के बाद से, इन डीपीएसयू ने अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए रास्ते तलाशना शुरू कर दिए हैं और अपने ग्राहक आधार तथा उत्पाद प्रोफ़ाइल में विविधता लाने की दिशा में उत्साहपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। पिछले एक साल के दौरान नई कंपनियों को 7,200 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के घरेलू ऑर्डर मिले हैं। नई कंपनियों की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां नीचे सूचीबद्ध की गई हैं:
- म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) को पिछले एक साल में विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद के लिए 1,500 करोड़ रुपये से अधिक के निर्यात ऑर्डर मिले हैं। ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल) को पैराशूट के निर्यात के लिए भी ऑर्डर मिले हैं।
- यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल) ने उत्पाद और ग्राहक विविधीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इससे उन्हें भारतीय रेलवे जैसे गैर-रक्षा बाजार से 300 करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर प्राप्त करने में मदद मिली है।
- ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल) ने एक आला बाजार में प्रवेश करने और लंबे समय तक अपने व्यवसाय को बनाए रखने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, बैलिस्टिक हेलमेट, ईसीडब्ल्यूसीएस आदि जैसी वस्तुओं को विकसित किया है।

- आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड (एवीएनएल) ने सीआरपीएफ के लिए डिजाइन किए गए माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल का एक नया संस्करण विकसित किया है, जो अन्य सशस्त्र बलों के लिए भी उपयोगी हो सकता है।
- एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूईआईएल) को दिल्ली पुलिस को जेवीपीसी कार्बाइन की पूर्ति का ऑर्डर मिला है।
- म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) पिनाका रॉकेट के नए वेरिएंट अर्थात पिनाका एमके-1 (एक्सटेंडेड रेंज) और डीपीआईसीएम को सफलतापूर्वक प्रूफ फायर करने में सक्षम रहा है।
- एमआईएल ने 40 एमएम यूबीजीएल गोला-बारूद, 500 किलोग्राम जनरल पर्पज बम और 76/62 एसआरजीएम एचईडीए गोला बारूद भी सफलतापूर्वक विकसित किया है।
- इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल) ने टैंकों के लिए ड्राइवर नाइट साइट्स विकसित की है जो फ्यूजन इमेजिंग की तकनीक के मामले में पहली बार है।

इन नई संस्थाओं ने अपने संसाधनों के अधिकतम उपयोग और लागत में कमी के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। उन्होंने ओवरटाइम और गैर-उत्पादन गतिविधियों के लिए व्यय में कमी और सौर ऊर्जा के उपयोग, जल पुनर्चक्रण, एलईडी पर क्रियांतरण आदि जैसे लागत में बचत के उपाय भी किए हैं।

इस अवसर पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान, थलसेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, सह नौसेनाध्यक्ष वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

एबीबी/डीएस